(b) An evaluation of the PDS In Kerala was sponsored by the Government in 1987 and was carried out by the Centre for Management Development, Thiruananthapuram. The report concluded that though PDS in Kerala is effective and consumers have .favourable disposition towards PDS, there is scope for making the PDS more effective by ever-coming the shortages/deficiencies such as unprofitable operations of fair price shops, malpractices by fair price shops and declining involvement of Co-operative sector in the PDS. This study report has not been published.

Persons detained under PBMMSEC Act, 1980

4251. SHRI RAMACHANDRAN PILLAI:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) how many persons have been detained under the Prevention of Black-marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 in States during 1992-93 and 1993-94;

(b) whether Government have conducted any study about the implementation of the Act; and

(c) if so, what are the findings ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) Calender year-wise information is listed below:—

Year	No. of detention
1972 . . .	172
1973 . . .	132
1994 . . .	22
(Up to 31-3-94)	

(b) No, Sir.

(c) Question does not arise.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सप्लाई की जा रही वस्तुओं का विक्रय मूल्य

4252. श्री रामजी : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सप्लाई की जाने वाली प्रत्येक वस्तु का प्रति क्विंटल विक्रय मूल्य क्या था और खरीद के लिए उनका समर्थन मूल्य क्या क्या था और प्रति वर्ष प्रति क्विंटल कितनी राज सहायता दी गई; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वस्तु का प्रति वर्ष कितनी मात्रा में वितरण किया गया और प्रत्येक वस्तु कतनी-कितनी मात्रा में घटी और उसके क्या कारण थे ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले चावल, गेंहू, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेलों, मिट्टी के तेल और सॉफ्ट कोक के केन्द्रीय निर्गम मूल्य निम्नवत् हैं :—

(रु० प्रति क्विंटल)

वस्तु	सार्वजनिक वितरण प्रणाली			
	से साधू	कॉमन	फाइन	सुपर फाइन
1	2	3	4	5
चावल	28-12-91	377	437	458
	11-1-93	437	497	518
	1-2-94	537	617	648
गेहूं	28-12-91	280		
	11-1-93	330		
	1-2-94	402		

1	2	3	4
			(रू० प्रति मी० टन)
		(थोक में)	(15 कि०ग्रा० के टिन में)
आयातित खाद्य तेल	26-1-91	16500	19000
	4-1-92	22000	25000
मिट्टी का तेल	25-7-91	रू० 2201.54 प्रति कि० लीटर (रू० प्रति कि०ग्रा०)	
लेवी चीनी (खुदरा)	24-7-91	रू० 6.10	
	21-1-92	रू० 6.90	
	17-2-93	रू० 8.30	
	1-2-94	रू० 9.05	

पिछले तीन वर्षों (1991-92, 1992-93 और 1993-94) के दौरान धान, गेहूं गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य/अधिप्राप्ति मूल्य निम्नवत है :—

(अधिप्राप्ति/समर्थन मूल्य (रू० प्रति क्विंटल)

	विपणन वर्ष			
	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
धान				
कॉमन	230	270	310	
फाइन	240	280	330	
सुपर फाइन	250	290	350	
गेहूं	225	275	330	350
गन्ना	26.00	31.00	34.50	37.00

पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के वितरण पर सरकार द्वारा वहन की गई राजसहायता की कुल राशि निम्नवत है :—

(करोड़ रुपयों में)

91-92 .	2850
92-93 .	2800*
93-94 (संशोधित अनुमान)	3650

*चीनी को मिला कर

(ख) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की उठाई गई मात्रा निम्नवत है :—

(लाख टन में)

	1991-92	1992-93	1993-94
चावल	98.60	91.58	81.19*
गेहूं	85.43	72.16	51.98*
लेवी चीनी	42.30	42.96	42.99
आयातित खाद्य तेल . . .	0.84	0.59	0.20*
मिट्टी का तेल	82.38	83.51	71.06**

*1993-94 में चावल, गेहूं और आयातित खाद्य तेल की उठाई गई मात्रा फरवरी, 1994 तक की है।

**मिट्टी के तेल की उठाई गई मात्रा जनवरी, 1994 तक की है।

खाद्यानों की उठाई गई मात्रा में कमी सामान्यतः खाद्यानों की खुले बाजार में बढ़ी हुई उपलब्धता के कारण हुई है।

खाद्य तेलों के आयात का सहारा केवल तभी लिया जाता है जब खाद्य तेलों के घरेलू मूल्यों में वृद्धि का रुख दिखाई पड़ता है।

Allocation of rice and sugar to Orissa

4253. SHRI RAHASBIHARI BARIK : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether there has been increase in the demand of rice and sugar by the consumers of Orissa;

(b) if so, the steps proposed to be taken to enhance rice and sugar allocation to Orissa;

(c) the projection made for 1994 ; and

(d) the steps taken in that direction so far ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS & PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUD-DIN AHMED) : (a) and (b) Allocation of wheat to Orissa was increased from 20,000 tonnes in October, 1993 to 25,000 tonnes in November, 1993 and again raised to 30,000 tonnes from March, 1994 to June, 1994. An additional allocation of 5,000 tonnes has been made to the state for a period of 4 months from May, 1994 to August, 1994. The allocation of rice to the state is 38,700 tonnes per month. Request for increase in the levy sugar allocation could not be acceded to due to constraints in the availability of levy sugar.

(c) and (d) All State Governments/ UT Administrations including Orissa, were requested to work out a realistic monthly schedule of requirement for the PDS taking into account the seasonal availability of foodgrains in the open market. Projection have not so far been received from the Government of Orissa.

Subsidised essential commodities under PDS in Bihar

4254. SHRI S. S. AHLUWALIA : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to provide specially subsidised essential commodities through PDS to most backward villages in the Country;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) how many of such villages are located in the State of Bihar; and

" (d) what steps Government have taken to ensure that special subsidy benefits do